concentrate plant at Silchar and the cost expected;

(b) the cost incurred till March 1995; and

(c) the present proposals about the future of the company?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) The originally fixed date for commissioning the plant was January, 1986 and the estimated cost was Rs. 207.00 lakhs.

(b) The cost incurred till March, 1995 is Rs. 281.26 lakhs.

(c) It has been decided to dispose of the plant at Silchar on "as is where is" basis.

**Preparation for Blue Print for Transport Sector**

334. DR. BAPU KALDATE:
SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI K.M. KHAN:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the World Bank has prepared a blue print for the improvement of the transport sector in India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) The World Bank has submitted a report on the long term issues in the Transport Sector in India. The report is a voluminous one covering 91 issues, in various transport sectors viz. Roads, Ports, Shipping, Road Transport, Railways, Civil Aviation and it has been examined in this Ministry. As a preliminary response, although the report has touched on some important issues, we have reservation about some of them. We agree that the various transport modes should develop in an integrated manner within the minimum resource outlay to match the demand for increased transport infrastructure. We realise that lack of transport infrastructure can be a serious constraint for economic growth. With the involvement of private sector utilising private sector funds through privatisation, we expect, we shall be able to meet the infrastructural requirements of the future adequately.

**विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों में हिन्दी का प्रयोग**

335. श्री विष्णु कान्त शास्त्री: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के बाहर स्थित भारत के राजदूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और अन्य कार्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) गत वर्ष इनमें से किन-किन राजदूतावासों और अन्य कार्यालयों में गत वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को हिन्दी में पढ़ा गया और वहां के अधिकारियों ने अपने-अपने भाषण हिन्दी में दिए; और

(ग) इन अवसरों पर हिन्दी की उपेक्षा होते रहने के क्या कारण हैं और राष्ट्रीय महत्व के इन समारोहों में हिन्दी के समुचित प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) भारत के 84 राजदूतावास, 27 हाई कमीशन, 27 प्रधान कौंसलावास, 2 कमीशन, 3 सहायक हाई कमीशन, 5 विशिष्ट मिशन हैं। ये कार्यालय विदेश मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन आते हैं। अन्य मंत्रालयों और विभागों के नियंत्रणाधीन कार्यालयों की निश्चित संख्या का पता लगाया जा रहा है तथा सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) गणतन्त्र दिवस और स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के भाषणों को केवल विदेश स्थित मिशनों और केन्द्रों को भेजा जाता है। भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से यह उम्मीद की जाती है वे मिशन/केन्द्र में आयोजित गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस समारोहों में भाग लें।